VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(23 January 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- 'स्टारगेट परियोजना': अमेरिका में AI बुनियादी ढांचे के निर्माण की 500 अरब डॉलर की परियोजना
- 'ड्रिल, बेबी, ड्रिल' नारा और डोनाल्ड ट्रम्प की 'राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल' योजना
- सैफ अली खान से जुड़ा 'शत्रु संपत्ति' मामला क्या है?
- MCQ

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

'स्टारगेट परियोजना': अमेरिका में AI बुनियादी ढांचे के निर्माण की 500 अरब डॉलर की परियोजना

चर्चा में क्यों है?

- अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बड़ी घोषणा की जो AI के भविष्य को आकार दे सकती है। एक कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि 'प्रोजेक्ट स्टारगेट' के तहत अमेरिका में AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 500 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा, जिससे 1 लाख से अधिक अमेरिकियों को तुरंत नौकरी मिलेगी।

- राष्ट्रपति ट्रम्प ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी AI इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना करार दिया है। उन्होंने कहा कि "यह परियोजना सुनिश्चित करेगी कि संयुक्त राज्य अमेरिका AI और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बना रहेगा"।

- कुछ नीति विशेषज्ञ अमेरिका के इस कदम को प्रौद्योगिकी को हथियार बनाने का तरीका मानते हैं, जिसके तहत वह अमेरिकी कंपनियों के स्वामित्व वाले बड़े भाषा मॉडल (LLM) से लेकर उसके आसपास के बुनियादी ढांचे तक, हर चीज पर नियंत्रण करना शुरू कर देगा।

स्टारगेट परियोजना क्या है?

- स्टारगेट परियोजना मूलतः एक नई कंपनी है जिसका लक्ष्य अगले चार वर्षों में अमेरिका में उन्नत AI अवसंरचना के निर्माण के लिए 500 अरब डॉलर का निवेश करना है। इस पहल में लगभग तुरंत 100 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा।
- प्रोजेक्ट स्टारगेट का उद्देश्य कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता (AGI) के विकास को आगे बढ़ाना है। यह परियोजना AI की प्रगति में एक महत्वपूर्ण छलांग है।
- उल्लेखनीय है कि सॉफ्टबैंक, Oracle, OpenAI और MGX इसके प्रमुख हितधारक हैं, जिसमें सॉफ्टबैंक वित्तीय पहलू को संभालेगा और OpenAI संचालन की देखरेख करेगा। मासायोशी सोन इसके अध्यक्ष होंगे, और प्रौद्योगिकी भागीदारों में Arm, Microsoft, NVIDIA, Oracle और OpenAI शामिल हैं।
- जब भौतिक बुनियादी ढांचे की बात आती है, तो निर्माण टेक्सास में शुरू हो गया है, और अमेरिका में अन्य स्थानों पर विस्तार करने की योजना है।

राष्ट्रपति ट्रंप की 'मेक इन अमेरिका' पहल पर बल:

- राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपनी "मेक इन अमेरिका" कहावत को कायम रखा और कहा, "हम जो करना चाहते हैं, वह यह है कि हम इसे इस देश में बनाए रखना चाहते हैं"। उन्होंने कहा कि चीन एक प्रतिस्पर्धी है और वह चाहते हैं कि अमेरिका अग्रणी बने।
- उन्होंने कहा कि "मैं आपातकालीन घोषणाओं के माध्यम से बहुत मदद करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास एक आपातकालीन स्थिति है, हमें यह सामान बनाना है। इसलिए उन्हें बहुत अधिक बिजली का उत्पादन करना है। और हम उनके लिए यह उत्पादन आसानी से करवाना संभव बना देंगे"।

भारत को भी AI अवसंरचना पर तेजी से काम करने की जरूरत:

- HCL के संस्थापक और नेशनल क्वांटम मिशन ऑफ इंडिया के मिशन गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष अजय चौधरी ने कहा, "रणनीतिक स्वायत्तता के लिए, हमें अपना खुद का AI सिद्धांत बनाना होगा और अपने डेटा को मजबूती से नियंत्रित करना शुरू करना होगा। साथ ही, हमें डेटा केंद्रों के लिए अपना खुद का घरेलू हार्डवेयर बनाना होगा क्योंकि हमारे डेटा को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होने वाला है"।

- चौधरी के अनुसार, सरकार और उद्योग को AI के लिए रणनीति बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। भारत वर्तमान में 10,000 करोड़ रुपये के 'इंडियाएआई' मिशन को क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें कंप्यूटिंग क्षमता, डेटासेट प्लेटफॉर्म, इनोवेशन सेंटर, सुरक्षित और विश्वसनीय AI, एप्लिकेशन डेवलपमेंट पहल आदि बनाना शामिल है। सरकार की महत्वाकांक्षा देश में एक संप्रभु AI क्षमता का निर्माण करना है, जो अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके AI विकसित करना है।
- हाल ही में, पिछली बिडेन सरकार ने AI चिप निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जिसके लागू होने पर भारत सहित अन्य देशों द्वारा आयात किए जा सकने वाले ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) पर अंकुश लग सकता है।

भारत में AI अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र आगे आये:

- एक उद्योग अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी निजी क्षेत्र स्टारगेट को वित्तपोषित कर रहा है। इसलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी समूह, टाटा जैसे बड़े घरेलू समूह भी धन का उपयोग कर सकते हैं और भारत के नेतृत्व वाली AI परियोजना शुरू कर सकते हैं। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है।
- उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार स्टारगेट परियोजना से सीख लेकर भारत अपने AI पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर अपनी AI पहल की अवधारणा बना सकता है और उसे लागू कर सकता है।

'ड्रिल, बेबी, ड्रिल' नारा और डोनाल्ड ट्रम्प की 'राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल' योजना:

चर्चा में क्यों है?

- संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में, डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने राष्ट्रपति अभियान के नारे में से एक को दोहराया - "ड्रिल, बेबी, ड्रिल" - यह दर्शाता है कि वह अमेरिका में अधिक तेल और गैस उत्पादन और खपत के लिए जोर देंगे। राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह भी कहा कि वह अमेरिकी तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने और कीमतों को कम करने के लिए "राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल" की घोषणा करेंगे।

'ड्रिल, बेबी, ड्रिल' नारे का इतिहास:

- 'ड्रिल, बेबी, ड्रिल' नारा 2008 में माइकल स्टील द्वारा गढ़ा गया था, जो अमेरिका के मैरीलैंड के पहले अफ्रीकी-अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर और रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के अध्यक्ष थे।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- माइकल स्टील के अनुसार, उन्होंने मध्य पूर्वी तेल से अमेरिका की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया था।
- उल्लेखनीय है कि माइकल स्टील ने 2008 में यह नारा उस समय दिया जब मध्य पूर्व में संघर्ष के कारण अमेरिका में ईंधन की कीमतें बहुत अधिक थीं।

राष्ट्रपति ट्रम्प की "राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल" के मायने:

- राष्ट्रपति ट्रम्प ने आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित करने का अर्थ है कि "आप उस समस्या से बाहर निकलने के लिए जो कुछ भी करना है, कर सकते हैं"। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्राधिकरणों को अनलॉक करेगा जो अमेरिका को फिर से तेजी से निर्माण करने, कोयला और प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन करने, नौकरियों का सृजन करने, समृद्धि बनाने और हमारे राष्ट्र की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में सक्षम बनाएगा।
- ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने से राष्ट्रपति को कुछ अतिरिक्त कार्यकारी शक्तियां मिलती हैं, जो राष्ट्रपति को कुछ पर्यावरणीय विनियमों को निलंबित करने या कच्चे तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देते हैं।

- उल्लेखनीय है कि अब तक अमेरिकी इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति ने कभी भी "राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल" घोषित नहीं किया है, लेकिन 1970 के दशक में क्षेत्रीय "ऊर्जा आपातकाल" घोषित किए गए थे, जब जीवाश्म ईंधन की कमी थी।
- तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने राज्य के राज्यपालों को परिणामस्वरूप कुछ पर्यावरण नियमों को निलंबित करने का अधिकार दिया, लेकिन उनसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए निहितार्थों के कारण "उचित सावधानी से कार्य करने" का आग्रह किया था।

क्या वर्तमान में अमेरिका में जीवाश्म ईंधन की कमी है?

- आपातकाल की घोषणा में ऊर्जा में तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, कोयला, जैव ईंधन, भूतापीय, बहता पानी और महत्वपूर्ण खनिजों को शामिल किया गया है - लेकिन सौर या पवन को शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने उद्घाटन भाषण में जीवाश्म ईंधन पर ध्यान केंद्रित किया है।
- उल्लेखनीय है कि अमेरिका में 70 के दशक में 'क्षेत्रीय ऊर्जा आपातकाल' जीवाश्म ईंधन की कमी के जवाब में थे। लेकिन वर्तमान में अमेरिका ईंधन की कमी का सामना नहीं कर रहा है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

अमेरिका पहले से ही सबसे बड़ा तेल उत्पादक:

- अमेरिका मध्य पूर्व से तेल पर निर्भर होने से बहुत आगे निकल आया है और वर्तमान में, उसके पास जीवाश्म ईंधन की कोई कमी नहीं है। वास्तव में, अब तक, अमेरिका दुनिया में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है, और जीवाश्म ईंधन का शुद्ध निर्यातक है। 2016 से, अमेरिकी तेल का उत्पादन 70% बढ़ गया है।
- अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार, 2024 में अमेरिका का कच्चे तेल का उत्पादन 13.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के वार्षिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया। इस साल उत्पादन में थोड़ी वृद्धि होने वाली है, जो 13.5 मिलियन बी/डी तक पहुंच जाएगी।
- इसी तरह, एलएनजी निर्यात 2016 में लगभग शून्य से बढ़कर अमेरिका वैश्विक अग्रणी बन गया है।

सैफ अली खान से जुड़ा 'शत्रु संपत्ति' मामला क्या है?

चर्चा में क्यों है?

- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनेता सैफ अली खान से केंद्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क करने को कहा है, जिसमें भोपाल में पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत वाली ऐतिहासिक संपत्तियों को "शत्रु संपत्ति" घोषित किया गया है।

- उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय 2015 से सैफ अली खान की चुनौती पर सुनवाई कर रहा था। वहीं पिछले साल 13 दिसंबर को, जब सरकार ने न्यायालय को बताया कि "शत्रु संपत्ति के संबंध में विवादों के निपटारे के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया है", तब न्यायालय ने कहा कि वे 30 दिनों के भीतर अपना प्रतिनिधित्व दायर कर सकते हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

सैफ अली खान ने उच्च न्यायालय में याचिका क्यों दायर की है?

- उल्लेखनीय है कि 1947 में, भोपाल रियासत पर नवाब हमीदुल्ला खान का शासन था। उनकी तीन बेटियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई। दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान भारत में ही रहीं और उन्होंने नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की, जिनके बेटे मंसूर अली खान 'टाइगर' पटौदी थे।
- साजिदा सुल्तान के पोते सैफ अली खान को भोपाल में संपत्तियों का एक हिस्सा विरासत में मिला। हालांकि, आबिदा सुल्तान का पाकिस्तान प्रवास सरकार के उस दावे का केंद्र बन गया, जिसमें उन्होंने संपत्तियों को "शत्रु संपत्ति" बताया।
- 2014 में, शत्रु संपत्ति विभाग के संरक्षक ने भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्तियों को "शत्रु संपत्ति" घोषित किया। सैफ अली खान ने संरक्षक के नोटिस को चुनौती दी।
- वर्ष 2016 में एक अध्यादेश जारी किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि उत्तराधिकारियों का इन संपत्तियों पर कोई अधिकार नहीं होगा।

शत्रु संपत्ति क्या होती है?

- शत्रु संपत्ति से तात्पर्य उन चल और अचल संपत्तियों से है, जो संघर्ष के समय "शत्रु राष्ट्र" के रूप में नामित देशों में प्रवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत में छोड़ी जाती हैं। 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों और 1962 में चीन-भारत युद्ध के बाद, भारत सरकार ने पाकिस्तान या चीन की राष्ट्रीयता अपनाने वालों के स्वामित्व वाली संपत्तियों और व्यवसायों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।
- भारत रक्षा अधिनियम, 1962 के तहत तैयार किए गए भारत रक्षा नियमों के तहत, ये संपत्तियाँ भारत के शत्रु संपत्ति के संरक्षक के पास निहित थीं। संरक्षक को भारत सरकार की ओर से इन संपत्तियों का प्रबंधन करने का काम सौंपा गया है।

शत्रु संपत्ति के अधिग्रहण के बाद उसका क्या होता है?

- शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए दिशा-निर्देश, 2018 भारत के लिए शत्रु संपत्ति के संरक्षक में निहित संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया को रेखांकित करते हैं।
- इस दिशा-निर्देश के तहत शत्रु संपत्तियों की एक विस्तृत सूची और उनका मूल्यांकन एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। जिला

मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता वाली मूल्यांकन समितियां सर्किल दरों और अन्य कारकों के आधार पर इन संपत्तियों का मूल्य निर्धारित करती हैं।

- वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों वाली 'शत्रु संपत्ति निपटान समिति' इस बारे में सिफारिशें प्रदान करती है कि संपत्तियों को बेचा जाए, हस्तांतरित किया जाए या बनाए रखा जाए। खाली संपत्तियों को सबसे अधिक बोली लगाने वाले को नीलाम किया जा सकता है, जबकि कब्जे वाली संपत्तियों को समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर मौजूदा रहने वालों को पेश किया जा सकता है। शेयर जैसी चल शत्रु संपत्तियाँ सार्वजनिक नीलामी, निविदाओं या अन्य स्वीकृत तरीकों से बेची जा सकती हैं।
- शत्रु संपत्ति का संरक्षक कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करता है और लेन-देन पूरा होने के बाद बिक्री प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसकी आय भारत के समेकित कोष में जमा की जाती है।

भारत में वर्तमान में कितनी शत्रु संपत्तियां हैं?

- 2 जनवरी, 2018 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने लोकसभा को बताया कि कुल 9,280 शत्रु संपत्तियां पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा और 126 चीनी नागरिकों द्वारा छोड़ी गई हैं। नवंबर 2018 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के शत्रु शेयरों को बेचने की प्रक्रिया को मंजूरी दी।

- 2020 में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह (GoM) ने 9,400 से अधिक शत्रु संपत्तियों के निपटान की निगरानी शुरू की, जिसका सरकार का अनुमान है कि इसकी कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपये है।

क्या कानूनी उत्तराधिकारी शत्रु संपत्ति के वारिस हो सकते हैं?

- शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत, शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित संपत्तियां स्थायी रूप से शत्रु संपत्ति के संरक्षक के पास रहती हैं, जिसमें उत्तराधिकार या हस्तांतरण की कोई गुंजाइश नहीं होती।
- शत्रु संपत्ति (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2017 ने कानून को सुदृढ़ किया और इसके दायरे का विस्तार किया। संशोधनों ने "शत्रु विषय" और "शत्रु फर्म" की परिभाषा को व्यापक बनाया, जिसमें कानूनी वारिस और उत्तराधिकारी शामिल हैं, चाहे उनकी नागरिकता कुछ भी हो, चाहे वे भारतीय हों या किसी गैर-शत्रु देश से।
- इन संशोधनों ने उत्तराधिकार के दावों को प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि ऐसी संपत्तियां अनिश्चित काल तक सरकार के नियंत्रण में रहेंगी।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

शत्रु संपत्तियों से जुड़े मामलों से अदालतें कैसे निपटती हैं?

- सबसे उल्लेखनीय मामलों में से एक उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद के राजा की संपत्ति के बारे में था। राजा, 1957 में पाकिस्तान चले गए और उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकता हासिल कर ली। हालांकि, उनकी पत्नी और बेटा भारत में नागरिक के रूप में रहे।
- 1968 के कानून के लागू होने के बाद, राजा की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। राजा की मृत्यु के बाद, उनके बेटे ने इसको चुनौती दी और संपत्तियों का स्वामित्व मांगा। 2005 में, सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के उत्तराधिकार के उसके अधिकार को मान्यता देते हुए बेटे के पक्ष में फैसला सुनाया।
- इस फैसले के कारण इसी तरह के कानूनी दावों में उछाल आया। मुकदमेबाजी की लहर ने सरकार के लिए इन संपत्तियों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा की।
- इस चुनौतियों से निपटने के लिए शत्रु संपत्ति (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2017, लाया गया। इस कानून ने न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि शत्रु संपत्ति संरक्षक के पास ही रहेगी, चाहे उत्तराधिकार के दावे हों या शत्रु की राष्ट्रीयता या स्थिति में कोई बदलाव हो।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQ

Q.1. चर्चा में रहे 'स्टारगेट परियोजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह अमेरिकी सरकार की 500 अरब डॉलर की AI अवसंरचना विकास की परियोजना है।
2. इस परियोजना का उद्देश्य कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता के विकास को आगे बढ़ाना है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b)

Q.2. हाल ही में खबरों में रहे 'इंडियाएआई' मिशन से जुड़े विभिन्न पिलरों में से निम्नलिखित कौन-सा/से उसमें शामिल है/हैं?

(a) AI कंप्यूटिंग क्षमता का विकास

(b) सुरक्षित और विश्वसनीय AI

(c) AI इनोवेशन सेंटर

(d) उपर्युक्त सभी।

Ans. (d)

Q.3. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में "राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल" की घोषणा किया है। अमेरिका के इस "राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अब तक अमेरिकी इतिहास में किसी भी अन्य राष्ट्रपति ने कभी भी "राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल" घोषित नहीं किया है।
2. वर्तमान में अमेरिका में जीवाश्म ईंधन की कमी के कारण ऊर्जा कीमतों में भारी वृद्धि के कारण इस ऊर्जा आपातकाल घोषित किया गया है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans. (a)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

Q.4. अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार अमेरिका 2018 से 2022 तक दुनिया का शीर्ष क्रूड आयल उत्पादक देश था। वर्तमान में अमेरिका में क्रूड आयल का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित किस राज्य में किया जा रहा है?

(a) अलास्का में

(b) कोलोराडो में

(c) न्यू मैक्सिको में

(d) टेक्सास में

Ans. (d)

Q.5. चर्चा में रहे 'शत्रु संपत्ति' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. वे चल और अचल संपत्तियां, जो युद्ध के समय "शत्रु राष्ट्र" के रूप में नामित देशों में प्रवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत में छोड़ी जाती हैं।

2. भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान या चीन की राष्ट्रीयता अपनाने वालों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c)